

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न संख्या : 2293

23 मई, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

संस्थागत जन्म/प्रसव

2293. श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यह बताने को कृपा करे कि:

- (क) सरकार ने देश में 100 फीसदी संस्थागत जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) संस्थागत जन्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में घाटिया और अमानवीय सुविधाओं के कारण अनेक महिलाएं असंस्थागत प्रसव का चुनाव करती हैं, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार को शहरी/नगरीय क्षेत्रों में असंस्थागत प्रसव के गंभीर मामले मिले हैं?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (श्रीमती चटर्जी)

(क): सरकार ने देश में 100 प्रतिशत संस्थागत जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।

(ख): देश में संस्थागत जन्म को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम अतुल्यक में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

- ₪ क्षेत्र ( ): सभी निवारण योग्य मातृ एवं नवजात मृत्युओं और अपंगताओं को समाप्त करने के लिए तथा सकारात्मक प्रसव अनुभव प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को आश्वसित, सत्कारपूर्ण, सम्मानजनक एवं निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचया, सेवाओं के मना करने के प्रति शून्य सहनशीलता के उद्देश्य वाली एक व्यापक, बहुआयामी एवं समन्वित नीति दृष्टिकोण है।
- ₪ प्रवर्ध क्षेत्र ( ) पीएमएसएमए के अंतर्गत, देश में सभी गभवती महिलाओं को प्रत्येक महीने को 9 तारीख को नियत दिवस, निःशुल्क, आश्वासन गुणवत्तायुक्त प्रसव-पूर्व परिचया प्रदान की जाती है।
- ₪ क्ष ( ) : संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल 2005 में एक मांग संवर्धक और सशत नकदी अंतरण स्कीम को प्रारंभ किया गया था।
- ₪ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) को गभवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए पॉकेट व्यय के व्यय को कम करने के लिए जून, 2011 में आरंभ किया गया था। इस पहल में सिर्जियन सेक्शन सहित निःशुल्क और बिना व्यय के प्रसव हेतु सावजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गभवती महिलाएं पात्र हैं।
- ₪ ष : लक्ष्य कार्यक्रम दिसंबर, 2017 में लेबर रूम और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में परिचया को गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गभवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और तत्काल बाद को अवधि में सम्मानजनक और गुणवत्ता देखभाल प्राप्त हो।
- ₪ मिडवाइफरी कार्यक्रम मिडवाइफरी कार्यक्रम नस प्रेक्टिशनर के एक संवर्धक, जो अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ संघ (आईसीएम) सक्षमताओं के अनुसार कुशल हैं और अनुकंपा आधार महिला केन्द्रित प्रजनन, मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य परिचया सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं, के सृजन के लिए 2018 में प्रारंभ किया गया था।
- ₪ : एफआरयू में आपातकाल प्रसूति परिचया के प्रावधान को देश में सभी एफआरयू को संचालित करके किया जा रहा है। जबकि महत्वपूर्ण घटकों जैसे कि काय संख्याबल, ब्लड स्टोरेज यूनिट, रेफरल लिंकज आदि के सुदृढीकरण पर जोर दिया गया है।
- ₪ उच्च मामलों को संख्या वाले केंद्रों में स्थित ( ) स्कंध स्थापित किए गए हैं ताकि माता एवं बच्चों को प्रदान की जाने वाली परिचया को गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
- ₪ चौबीस घंटे बुनियादी और व्यापक प्रसूति परिचया प्रदान करने के लिए उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों का संचालन।
- ₪ द व्यापक आरएमएनसीएचएन सेवाओं के प्रावधान के लिए अवसंरचना, उपकरण और प्रशिक्षित काय संख्याबल के संदर्भ में देश में 25,000 से अधिक "डिलीवरी पॉइंट्स" का सुदृढीकरण किया गया है।

- ¶ ऑब्स्टेट्रिक : जटिल गभावस्थाओं से निपटने के लिए देश में अधिक लोड वाली तृतीयक परिचया सुविधाओं के मामले में ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू/एचडीयू का संचालन किया जा रहा है।
- ¶ मदर एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम ( ): समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक गभवती महिला और बच्चे को ट्रैक करने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली शुरू की गई है।
- ¶ दक्ष और दक्षता पर स्वास्थ्य परिचया प्रदाताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों को कमी को दूर करने के लिए एनेस्थीसिया (एलएसएस) और सी-सेक्शन सहित ऑब्स्टेट्रिक केयर (सीईएमओएनसी) विषयों पर एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए क्ष ।

\*\*\*\*\*